भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1475
उत्तर देने की तारीख 04 दिसम्बर, 2024

वाई-फाई और तीव्र गति वाले नेटवर्क

1475. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र के कई दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में वाई-फाई और अन्य तीव्र गति वाले नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इससे स्थानीय नागरिकों को काफी कष्ट और परेशानी हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या नेटवर्क की कमी के कारण वहां पीओएस मशीनें काम नहीं करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप समय पर राशन वितरित नहीं किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टावर संस्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थापित मोबाइल टावरों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) महाराष्ट्र के 43,931 गांवों (गांव के आंकड़े भारत के महारजिस्ट्रार के अनुसार) में से लगभग 41,514 गांवों में मोबाइल कवरेज है और इनमें से 40,526 गांव 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर किए गए हैं।

सरकार महाराष्ट्र सहित देश के ग्रामीण, जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में 4जी मोबाइल टावरों की संस्थापना के माध्यम से दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए डिजिटल भारत निधि (पूर्ववर्ती यूएसओएफ) के तहत विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। 4जी सेचुरेशन

परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र सहित देश के सेवा से वंचित 24,680 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। इस परियोजना में पुनर्वास, नई बस्तियों, मौजूदा प्रचालकों द्वारा सेवाएं देना बंद करने आदि के कारण 20% अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है।

सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड सेवाओं जैसे वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन आदि के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा नेटवर्क को अपग्रेड करने और मांग के आधार पर लगभग 3.8 लाख गैर-ग्राम पंचायत गांवों को कनेक्टिविटी सहित रिंग टोपोलॉजी में देश की सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी है।

(घ) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसमें ईपीओएस उपकरणों में नेटवर्क की अनुपलब्धता की स्थिति में ऑफलाइन फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) लेनदेन (बायोमेट्रिक सत्यापन के बिना) को रिकॉर्ड करने की सुविधा उपलब्ध है और यह सुविधा सभी ईपीओएस उपकरणों में उपलब्ध है।

(ङ) डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्तपोषित 4जी सेचुरेशन परियोजना सहित विभिन्न परियोजनाओं के तहत महाराष्ट्र के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में 1,093 टावर संस्थापित किए गए हैं जिनमें से 25 टावर धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लगाए गए हैं।

(च) पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा संस्थापित मोबाइल टावरों का जिला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

"वाई-फाई और तीव्र गति वाले नेटवर्क" के संबंध में माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए दिनांक 4 दिसंबर, 2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1475 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा संस्थापित मोबाइल टावरों का जिला-वार ब्यौरा :

क्र.सं.	**जिला**	**पिछले 5 वर्षों के दौरान जिले के ग्रामीण क्षेत्र में संस्थापित मोबाइल टावरों की संख्या**
1	अहमदनगर	1,090
2	अकोला	251
3	अमरावती	485
4	बीड	667
5	भंडारा	161
6	बुलढाणा	578
7	चंद्रपुर	192
8	छत्रपति संभाजीनगर	738
9	धाराशिव	456
10	धुले	354
11	गडचिरोली	462
12	गोंदिया	247
13	हिंगोली	195
14	जलगांव	702
15	जालना	466
16	कोल्हापुर	807
17	लातूर	546
18	नागपुर	536
19	नांदेड़	665
20	नंदुरबार	295
21	नासिक	1,009
22	पालघर	433
23	परभणी	382
24	रायगढ़	524
25	रत्नागिरि	379
26	सांगली	585
27	सतारा	754
28	सिंधुदुर्ग	156
29	सोलापूर	889
30	ठाणे	471
31	वर्धा	145
32	वाशीम	137
33	यवतमाल	528
कुल		**16,285**

*****